

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 698 / 2013 / बीकानेर

मैसर्स राजकमल एण्टरप्राइजेज,  
इण्ड. एरिया, बीकानेर  
बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 393/आरवैट/बीकानेर/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) के प्रयोजन से भिन्न रूप से खरीदे गये माल का प्रयोग करने के कारण रूपये 46,263/- रिवर्स कर आरोपित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा करमुक्त(चूरी) माल का निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर आईटीसी क्लेम आलौच्य अवधि में लिया गया, किन्तु आरवैट की धारा 18 के अन्तर्गत करमुक्त(चूरी) माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर आगतकर देय नहीं होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा आनुपातिक आधार पर कुल रिवर्स कर रूपये 46,263/- आरोपित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध कुल मांग रूपये 46,263/- आरोपित की गयी जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा दाल का निर्माण किया गया है न कि चूरी का, चूरी एक सह उत्पाद है। अतः अपीलार्थी द्वारा जो आईटीसी क्लेम किया गया है वह विधिक रूप से सही है। अपीलार्थी द्वारा दाल का

1/2

मुख्य उत्पाद तैयार किया जाता है तथा इस निर्माण प्रक्रिया से सह उत्पाद के रूप में चूरी प्राप्त होती है जो कि अधिनियम में करमुक्त होने से उसका कर मुक्त विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा करमुक्त माल के निर्माण में कच्चा माल प्रयुक्त किया है जिस पर उसके द्वारा आईटीसी क्लेम विधिक रूप से किया गया है तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बाईप्रोडक्ट के रूप में छिलका का उत्पादन भी किया गया। अतः अधिनियम की धारा 18(1)(e) के अन्तर्गत आनुपातिक रूप से रिवर्स किया गया आगतकर अनुचित है क्योंकि व्यवसायी का उद्देश्य करमुक्त माल बनाना नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया कि सक्षम अधिकारी द्वारा आगतकर रिवर्स करने हेतु खरीद मूल्य का अनुमान भी उचित रूप से नहीं किया गया है। उक्त सभी तथ्यों, आधारों पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया एवं मूल पत्रावली एवं पारित कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि जब अधिनियम की धारा 18(1)(जी) में कर योग्य एवं करमुक्त माल के उत्पादन के संबंध में आगतकर आनुपातिक रूप से स्वीकार होने का प्रावधान उल्लेखित है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स प्रा.लि. के प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.12.2011 महत्वपूर्ण है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान वैट कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1)(जी) में आनुपातिक रूप से आगतकर स्वीकार करने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः आगतकर केवल करयोग्य माल के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर ही देय होगा करमुक्त माल के उत्पादन हेतु क्रय किये गये माल पर नहीं। ऐसी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा करमुक्त माल के अनुपात में आगतकर रूपये 46,263/- रिवर्स किया गया है वह पूर्णतः उचित है।

उभयपक्षय बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवम् उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कर मुक्त माल चूरी का विक्रय किया गया है एवम् उक्त विक्रय के कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में क्लेम किये गये इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय नहीं है। जैसाकि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:-

".....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section." इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-


"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स प्रा.लि. के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2011 में प्रतिपादित मत का अनुसरण करते हुए निष्कर्ष दिया है कि "राजस्थान वेट कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1)(जी) के आनुपातिक रूप से आगतकर स्वीकार करने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः आगतकर केवल कर योग्य माल के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर ही देय होगा, कर मुक्त माल के उत्पादन हेतु क्रय किये गये माल पर नहीं। ऐसी दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा कर मुक्त माल के अनुपात में आगतकर रु. 46,363/- रिवर्स किया गया है वह पूर्णतः उचित है"।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2013 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य